

वैश्विक कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

किरण कुमारी*, डॉ.मनीषा दुवे**

शोध सारांश :

कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। अन्य देशों की भांति भारत देश के समक्ष भी कई प्रमुख चुनौतियां हैं जैसे- वायरस के प्रति समझ को बढ़ाना, दवा एवं वैक्सीन के विकास, रोग के निदान के लिए उपकरणों के विकास, संक्रमण रोकने के उपाय, जागरूकता इत्यादि। कोविड-19 महामारी की इस जंग के अग्रिम पंक्ति में हमारे देश के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडियाकर्मी तथा सैकड़ों स्व-सहायता समूह के सदस्य एक योद्धा के रूप में सामने आए हैं। इस जंग में 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' से जुड़ी स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं ने देश में बढ़ती स्वास्थ्य क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए मास्क, सेनिटाइजर और सुरक्षात्मक उपकरणों के उत्पादन एवं बीमारी से संबंधित जानकारी देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र एक वैश्विक कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है और कोरोना महामारी के रोकथाम, रणनीतियों एवं नवाचारों का सार प्रस्तुत करता है जिनकी अगुवाई स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों ने कोरोना महामारी के बीच की थी। इस शोध-पत्र के दो प्रमुख केंद्र-बिंदु हैं जिनके अंतर्गत कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका एवं महामारी के समय समूहों की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। इस अध्ययन के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष यह बताते हैं कि कोरोना के कठिन समय में भी स्वयं-सहायता समूहों ने सरकार के सभी निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के साथ-साथ सरकार के सामने आई स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन जरूरतों को भी पूरा किया है।

विषय संकेत – कोविड-19, स्वयं-सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

परिचय :

हम सभी जानते हैं कि समय-समय पर प्रकृति द्वारा जनित अनेक आपदाओं ने मानवीय अस्तित्व को मुश्किल में डाला है, विशेषकर प्रकृति में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न भिन्न-भिन्न रोगों ने मानव जीवन और मानव सभ्यता को विनाश के समक्ष कई बार लाया है लेकिन बदलते समय के साथ वैज्ञानिक अविष्कारों और चिकित्सा पद्धति में हुए उन्नत विकास ने जीवन को ऐसे अनेकों जानलेवा रोगों से बचाया है। फिर भी अनेकों बार ऐसी बीमारी या रोग ने एकाएक ही जन्म लिया है जिसके बारे में चिकित्सा विज्ञान में कोई भी सही जानकारी नहीं होती है और कोई सटीक तत्कालीन उपचार भी नहीं होता है और जो जीवन के लिए घातक हो

* शोध छात्रा (अर्थशास्त्र विभाग) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र विभाग) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

जाती है। ऐसे ही एक विषाणु जनित रोग ने पूरे विश्व को 2019 (दिसम्बर) में अपनी चपेट में लिया जिसे 'कोविड-19' कहा गया है। कोरोना (कोविड-19) महामारी चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ और इस महामारी ने कुछ ही महीनों के भीतर लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। भारत में कोरोना महामारी का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल राज्य में रिपोर्ट किया गया था। देश में यह महामारी छोटी संख्या से आरंभ होकर लाखों तक पहुंच गई एवं बड़ी संख्या में मौतें भी हुई हैं। कोरोना महामारी ने न केवल हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के सामने संकट खड़ा किया है, बल्कि पूरे विश्व में एक आर्थिक संकट को जन्म भी दिया है जिससे पूरे विश्व को आर्थिक मंदी के कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। विश्व की महाशक्तियां इस महामारी के नियंत्रण के लिए कई सारी रणनीतियां बना रही हैं जिसमें कुछ रणनीति सफल हुई तो कुछ रणनीति असफल साबित हुई हैं। इस संकट काल की स्थिति में भारत सरकार पूरे देश में एकजुटता और दृढ़ता के साथ कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में कोरोना महामारी नियंत्रण में है और यहां स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। व्यापक रणनीति, उचित संख्या में चिकित्सा जांच, उपचार एवं देश में कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर किये जा रहे बेहतर सुरक्षात्मक कार्य एवं प्रबंध के चलते संकट के इस काल में भी हमारा देश पूरे आत्मविश्वास के साथ डटकर मुकाबला कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में हमारे देश की लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायत, गांव से जुड़े अन्य कर्मचारी, आशा कार्यकर्ताओं एवं देशभर में 63.8 लाख स्वयं सहायता समूह तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 7.02 करोड़ महिलाओं का अभुतपूर्व योगदान रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 14,522 स्वयं-सहायता समूहों में शामिल 65,936 सदस्यों ने 399 जिलों में 30 मार्च 2020 तक 132 लाख मास्क को तैयार किया एवं बाद के महीनों में 27 लाख से अधिक महिलाएं 27 राज्यों में 10 करोड़ मास्क बनाने में शामिल हुईं तथा 3 लाख लीटर से अधिक सैनिटाइजर और लगभग 50,000 लीटर हैंडवॉश के उत्पादन में भी मदद की है।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन करना तथा महामारी के समय स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करना है।

शोध-प्रविधि :

यह अध्ययन विशुद्ध रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है और इसकी प्रकृति अवधारणात्मक है। द्वितीयक समंको के लिए मुख्यतः महिला बालविकास विभाग, नाबार्ड बैंक की रिपोर्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वेबसाइट, W.H.O की रिपोर्ट, इंटरनेट, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, अप्रकाशित शोध प्रबंध, आदि संबंधित वेबसाइटों का प्रयोग कर आकड़े एकत्रित किए गए हैं।

स्वयं-सहायता समूह :

स्वयं-सहायता समूह ग्रामीणों, निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है, जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी चाहे बचत आसानी से कर सकते हैं तथा उसका अंशदान उत्पादक, उपभोग अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए तैयार होते हैं। इन समूहों में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं। भारत में स्वयं सहायता समूह का उदय गुजरात राज्य में 'सुश्री इला भट्ट' के नेतृत्व में 1974 में महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं-सहायता समूह का सफल प्रयास माना जाता है। उसके पश्चात नाबार्ड ने

भारत में वर्ष 1986-87 में स्वयं-सहायता समूह की शुरुआत की थी। सन् 1999 में, भारत सरकार द्वारा एस.एच.जी. के गठन और कौशल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) की शुरुआत की गई जो एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान में नाबार्ड बैंक की रिपोर्ट (2020) के अनुसार पूरे भारत में 1,02,43,323 करोड़ स्वयं-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

महिला सशक्तिकरण :

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित-परिष्कृत कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सु-अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। महिला सशक्तिकरण को बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है- महिला सशक्तिकरण वह अवधारणा, सिद्धांत या आवश्यकता है, जिससे नारी को शिक्षित एवं जागरूक बनाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक जानकारी प्रदान कर ज्यादा जबाबदेह बनाया जा सकता है। इससे उनमें समता, स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो आएगी ही इसके अलावा यह अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय और अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि की लड़ाई खुद-ब-खुद लड़ सकेगी एवं इसके परिणामस्वरूप नारी जीवन की हर बाधाओं को पार कर विकास की दिशा में अग्रसर होंगी। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य होता है महिलाओं को शक्ति प्रदान करना जिससे वे हमारे समाज में पीछे न रह सकें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फैसलें ले सकें तथा गर्व से अपना सिर उठाकर चल सकें। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। भारतीय समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है। यहां महिलाओं को हमेशा से दूसरे दर्जे का माना जाता है। पहले महिलाएं परिवार और समाज के लिए एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं समझी जाती थीं। ऐसा माना जाता था कि उसे हर कदम पर पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब वर्तमान भारत में महिला उत्थान को महत्व का विषय मानते हुए कई प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण के कार्यों में तेजी भी आई है। आज की नारी अब जागृत और सक्रीय हो चुकी है। अतः कह सकते हैं कि 'नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ीयों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी' वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में अभी और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लागू एक प्रमुख योजना है। इसका लक्ष्य प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं-सहायता समूह के नेटवर्क में लाकर उनका वित्तीय समावेशन और आजीविका अर्जन के गतिविधियों में सहयोग सुनिश्चित कर ग्रामीण निर्धनों की आय बढ़ाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के तहत जुलाई 2020 तक 7.14 करोड़ महिलाओं के साथ लगभग 66 लाख महिला स्वयं-सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है।

कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका :

कोरोना महामारी शुरू होने और मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद से डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण निर्धन महिलाओं ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान दिया है। सिलाई में प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त महिला सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभागों के परामर्श का पालन करते हुए निर्धन और जरूरतमंदों के लिये मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवॉश, सुरक्षा-किट का निर्माण तथा सामुदायिक रसोई, सूखी राशन सामग्री, फल और सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसलिए कह सकते हैं कि महामारी संकट की मौजूदा स्थिति में भी भारत के 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में, शहरों की रोशनी से दूर, एसएचजी महिलाएं फेसमास्क का उत्पादन कर रही हैं, सामुदायिक रसोई चला रही हैं, आवश्यक खाद्य आपूर्ति कर रही हैं, लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रही हैं और गलत सूचनाओं का मुकाबला भी कर रही हैं।

मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी को पूरा करना :

24 जुलाई 2020 तक 29 राज्यों की 58,581 स्वयं सहायता समूहों की 2.96 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने मिलकर 22.47 करोड़ से अधिक मास्क का उत्पादन किया है। 17 राज्यों की 13,662 महिला सदस्यों ने 4.8 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन एवं 10 राज्यों की 1,790 महिला सदस्यों द्वारा 1.02 लाख लीटर हैंडवॉश का उत्पादन तथा 13 राज्यों की 6,585 महिला सदस्यों ने 35.61 लाख सुरक्षा कीटों का उत्पादन किया है। इस तरह से स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों ने महामारी के दौरान बढ़ती सुरक्षात्मक उपकरणों की मांग के तत्कालीन पूर्ति करने में अहम योगदान दिया है।

सामुदायिक रसोई चलाना :

समूह की महिला सदस्यों ने 4 राज्यों में 12,000 से अधिक सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की और जरूरतमंदों को 6 करोड़ से अधिक भोजन थाली उपलब्ध कराई है। इस व्यवस्था में किसी को भी भूखा ना जाने दिया जाए इस पर विशेष ध्यान रखा गया है।

जागरूकता फैलाना :

महिला स्वयं-सहायता समूहों के सदस्य गावों में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ-सफाई बनाये रखने के महत्व को समझा रहें और साथ ही साथ जरूरी सलाह भी दे रहें हैं जैसे-संक्रमण के लक्षण, जरूरी एहतियात, बार-बार हाथ धोने की जरूरत, बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों की देखभाल, मास्क लगाने और पोषक भोजन के बारे में जागरूक करना इत्यादि।

बैंकिंग और पेंशन सेवाएं प्रदान करना :

मार्च 2020 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और पेंशन सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एस.एच.जी. के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. ने 23 जून 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) के अंतर्गत 20.65 करोड़ प्रधानमंत्री जन-धन योजना की महिला खाताधारकों को 500 रु. प्रतेक की तीन किस्तों में (अप्रैल,मई, जून 2020) 30,956.90 करोड़ रुपए अंतरित किये हैं। 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू होने और आवाजाही की पाबंदियां लगाने के बाद बीसी सखी

(व्यवसाय अभिकर्ता बीसी प्वाइंटस के रूप में एसएचजी सदस्य) ने ग्रामीण आबादी से संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महामारी संकट के दौरान भी घर-घर जाकर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम के अंतर्गत बैंकिंग अभिकर्ता सखी (बीसी सखी) लॉकडाउन और गतिविधि संबंधी चुनौतियों के बावजूद बैंकिंग लेनदेन करती रही हैं। 15 राज्यों की लगभग 6,934 बीसी सखियों ने 31 जुलाई 2020 तक पी.एम.जी.के.वाई., अन्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वितरण के लिये 1845.76 करोड़ रुपये मूल्य के 83.63 लाख लेनदेन किये हैं। इन बीसी सखियों ने कोरोना महामारी संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का भी पालन किया है। देश में कुल मिलाकर 11,189 से अधिक एस.एच.जी. सदस्यों को बीसी सखियों के रूप में जिम्मेदारी दी गयी है। एस.एच.जी. की महिलाओं ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से लोगों को जोखिम से अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए। यह कार्यक्रम या तो ऑनलाइन या एस.एच.जी. बैठकों के जरिए या फिर घर-घर जाकर संचालित किये गये। इसके लिये विभिन्न मंत्रालयों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख संदेश और अन्य निर्देश सहित हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार प्रचार सामग्री और विज्ञापनों का उपयोग किया गया। इन प्रशिक्षित समुदाय संसाधन सदस्यों ने (24 जुलाई 2020 तक) 48.23 लाख स्वयं सहायता समूहों के 509.75 लाख सदस्यों को और 3.24 लाख गांवों में ग्रामीण परिवारों को प्रशिक्षण दिया एवं उन राज्यों में जहां प्रवासी कामगार कोरोना महामारी के कारण अपने गांवों में वापस लौटे थे उनके साथ मिलकर समूहों की महिलाएं एवं समाजिक कार्यवाई समिति के सदस्य और उनके परिसंघ के नेताओं ने कोरोना महामारी संकट के दौरान श्रमिकों को सुरक्षा और एहतियाती उपायों का निर्देश देने का कार्य प्रमुखता से किया है।

कोरोना महामारी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में स्वयं-सहायता समूहों की पहल :

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) के तहत देश के 399 जिलों को कवर करते हुए 24 राज्यों में स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा फेस मास्क बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत विभिन्न राज्यों द्वारा उत्पादित फेस मास्क को तालिका द्वारा दर्शाया गया है -

तालिका 1 : राज्यों द्वारा उत्पादित फेस मास्क

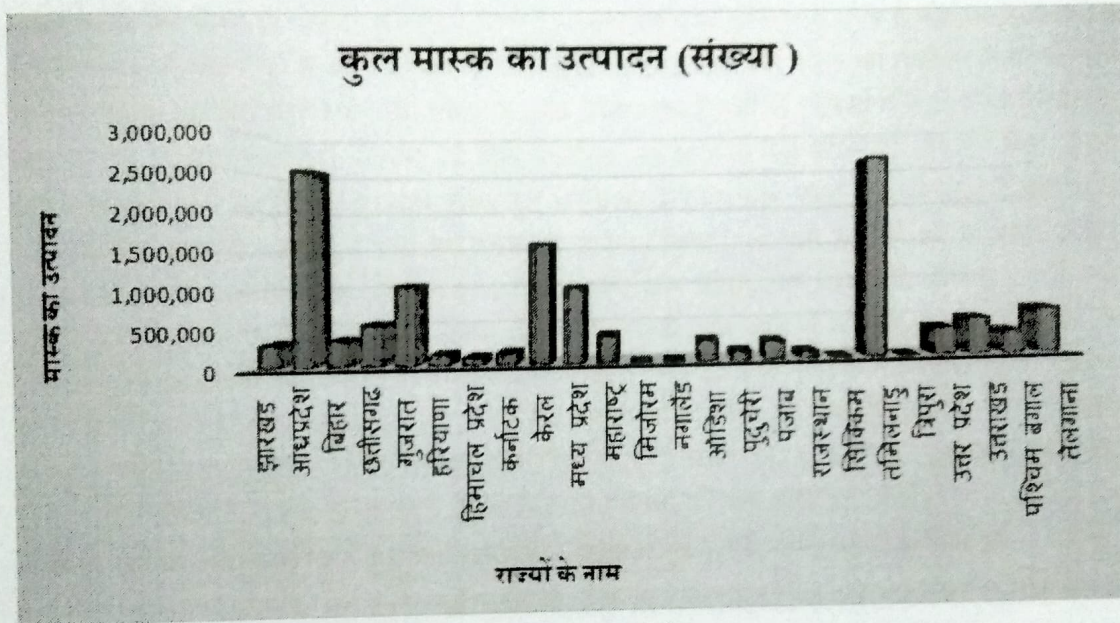
क्रम.स.	राज्यों के नाम	फेस मास्क का उत्पादन (दिनांक)	जिलों की संख्या	मास्क के उत्पादन में सामिल एसएचजी की संख्या	मास्क के उत्पादन में सामिल एसएचजी सदस्यों की संख्या	कुल मास्क का उत्पादन (संख्या)	मास्क के कुल उत्पादन के प्रतिशत(%)
1	झारखंड	22 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	21	131	394	3,00,215	2.27
2	आंध्रप्रदेश	25 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	5	4281	21,028	25,41,440	19.24
3	बिहार	22 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	34	271	1,084	3,49,517	2.65
4	छत्तीसगढ़	26 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक	24	932	2,674	5,49,712	4.16

वैश्विक कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

5	गुजरात	23 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	33	367	1,470	10,49,319	7.95
6	हरियाणा	13 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक	6	48	234	1,46,800	1.11
7	हिमाचल प्रदेश	25 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक	8	150	370	1,00,000	0.76
8	कर्नाटक	23 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	12	139	581	1,56,155	1.18
9	केरल	15 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	14	306	1,570	15,77,770	11.95
10	मध्य प्रदेश	19 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक	52	1511	4,652	10,04,419	7.61
11	महाराष्ट्र	24 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	25	602	2,558	3,62,332	2.74
12	मिजोरम	27 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	1	1	1	100	0.0007
13	नगालैंड	28 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	5	48	475	6,819	0.05
14	ओडिशा	20 मार्च 2020 से 1 अप्रैल 2020 तक	12	202	1,388	2,78,076	2.11
15	पुदुचेरी	17 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	2	143	303	1,20,380	0.91
16	पंजाब	21 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	15	575	2,536	2,43,268	1.84
17	राजस्थान	27 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	6	1206	6,297	92,890	0.70
18	सिक्किम	31 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	1	25	250	10,000	0.08
19	तमिलनाडु	26 मार्च 2020 से 4 अप्रैल 2020 तक	32	1927	10,780	26,01,735	19.70
20	त्रिपुरा	30 मार्च 2020 से 4 अप्रैल 2020 तक	4	45	173	4,650	0.04
21	उत्तर प्रदेश	28 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	49	968	2,027	3,64,894	2.76
22	उत्तराखण्ड	26 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	10	112	421	4,74,490	3.59
23	पश्चिम बंगाल	28 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक	17	284	2,190	2,91,794	2.21
24	तेलंगाना	18 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक	11	248	2,480	5,80,000	4.39
कुल			399	14,522	65,936	1,320,6775	100

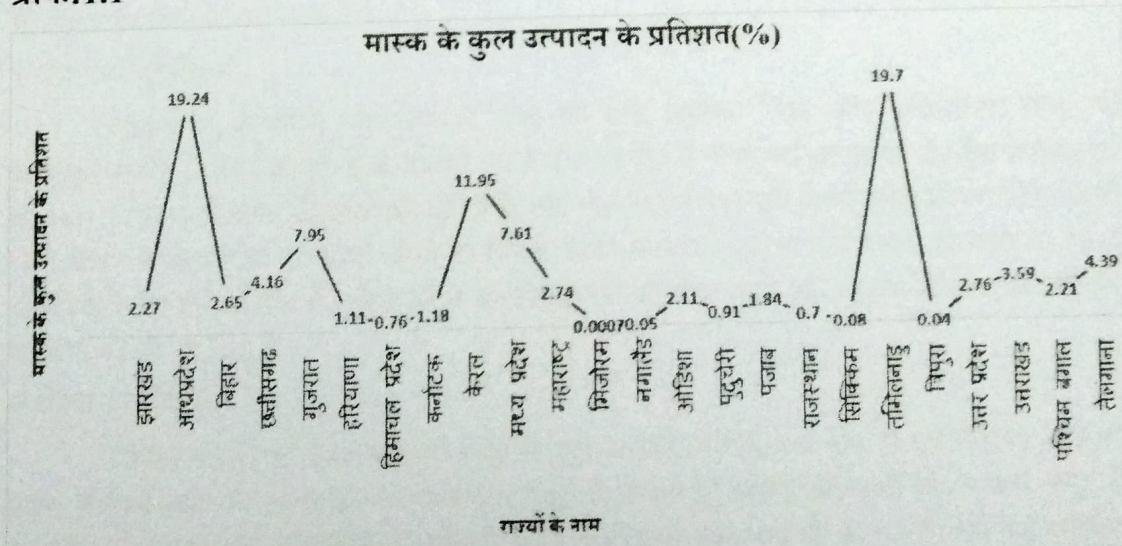
स्रोत :- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (प्रविष्ट तिथि : 09 APR 2021 Delhi)

ग्राफ: 1



स्रोत :- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (प्रविष्ट तिथि : 09 APR 2021 Delhi)

ग्राफ:1.1



स्रोत :- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (प्रविष्ट तिथि : 09 APR 2021 Delhi)

तालिका:1 के अनुसार झारखंड राज्य के स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों ने सबसे पहले कदम उठाया और 22 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक 21 जिलों के 131 स्वयं-सहायता समूहों के 394 सदस्यों ने मिलकर

वैश्विक कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

3,00,215 फेस मास्क का उत्पादन किया जो कुल उत्पादन का 2.27 प्रतिशत है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सबसे ज्यादा फेस मास्क के उत्पादन में शीर्ष 2 राज्य हैं - पहले स्थान पर तमिलनाडु राज्य है जहाँ पर 32 जिलों में 1,927 स्वयं-सहायता समूह के 10,780 सदस्यों ने मिलकर 26,01,735 फेस मास्क का उत्पादन किया जो कुल उत्पादन का 19.70 प्रतिशत है तथा दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ के 5 जिलों में 4,281 स्वयं-सहायता समूह से जुड़े 21,028 सदस्यों ने मिलकर 10 दिनों में क्रमशः 25,41,440 फेस मास्क का उत्पादन किया है जो कुल उत्पादन का 19.24 प्रतिशत है। वहीं सबसे कम मास्क का उत्पादन करने वाला राज्य मिजोरम है जहाँ पर 1 स्वयं-सहायता समूह के 1 सदस्य ने 100 फेस मास्क का उत्पादन किया है जो कुल उत्पादन का लगभग 0.0007 प्रतिशत है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के कई राज्यों के एस.एच.जी के सदस्य भी मास्कों का उत्पादन करने में शामिल हुए हैं। तालिका के अनुसार कुल 24 राज्यों द्वारा 14,522 स्वयं-सहायता समूहों से जुड़े 65,936 सदस्यों ने मिलकर कुल 1,320,6775 फेस मास्क का उत्पादन किया है, ये मास्क विभिन्न राज्यों में जिला कलेक्टर के परिसरों और रियायती मेडिकल स्टोर्स में 10/- रुपये की किफायती कीमत पर बेचे जा रहे हैं इससे समूह के सदस्यों को महामारी के संकट समय में भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो पा रहा है जिससे ये अपने परिवारों की देख-भाल कर रही हैं।

कोरोना महामारी के समय स्वयं-सहायता समूह के महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ :

कोरोना महामारी के इस जंग में स्वयं-सहायता समूह की महिलाएं जितना बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं तथा अपना योगदान दे रही उतना ही इन समूह की महिलाओं को लॉकडाउन की घोषणा तथा इस महामारी के समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। इन महिलाओं ने सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की समस्याओं का सामना किया है -

सामाजिक चुनौतियाँ :

लॉकडाउन के कारण स्वयं-सहायता समूह की सभी नियमित बैठकें और गतिविधियाँ समय की अनिश्चित अवधि के लिए बंद हो गई हैं, जिससे महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रही हैं (खेत के काम को छोड़कर) उनकी घर से बाहर की जगह खो-सी गई हैं, जहाँ पर महिलाएं एक साथ आकर घरेलू शोषण सहित अपने निजी जीवन के समस्याओं को साझा करती थी जिससे उनकी समस्याओं का सामाधान प्राप्त हो पाता था, परन्तु इस बैठक के बंद होने के साथ ही महिलाओं ने अपने अनुभावों को साझा करने और समर्थन पाने का एक समुदाय के स्थान को खो-सा दिया है।

आर्थिक चुनौतियाँ :

वर्तमान में कोई भी स्वयं-सहायता समूह से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं यानी कोई भी बैठक, कोई भी बचत तथा कोई भी ऋण का संवितरण नहीं हो पा रहा है। जिससे महिलाओं को घर खर्च, समूह से तथा बैंको से लिए गए ऋण की वापसी की समस्या, बचत ना हो पाना तथा आय की कमी आदि जैसे कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

कोरोना महामारी के कारण समूह से जुड़ी महिला सदस्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आजीविका मिशन द्वारा सरकार एवं निजी संस्थाओं के

साथ सहभागिता कर रोजगार के विकल्प , नए रोजगार हेतु प्रशिक्षण , वित्तीय सहायता , तकनीकी सहयोग समूहों की महिलाओं को किया जा रहा है, एवं वित्तीय सहायता को अधिक सरल बनाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी को तैनात करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

निष्कर्ष :

स्वयं-सहायता समूह न केवल एक समुदाय या समाज के बाहरी स्वरूप को बदलते हैं बल्कि सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ समाज में रहने वाले लोगों के विचारों को भी बदलते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना-संकट के इस मुश्किल घड़ी में स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं ने जिस प्रकार अपना योगदान दिया है उसको नकारा नहीं जा सकता। समूह की महिलाएं कोरोना के इस जंग में एक योद्धा के रूप में सामने आई है और देश के साथ डट कर खड़ी है। एम.एच.जी के सभी सदस्य सरकार के निर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके तथा इसके साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से लोगों को मास्क का उपयोग करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा उपायों के रूप में बार-बार हाथ धोने के लिए जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। इन महिलाओं की सहभागिता को देख कर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री 'श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोरोना काल में अभूतपूर्व सेवाओं के लिए महिला स्वयं-सहायता समूहों की सराहना भी की है'। लेकिन कोरोना वायरस महामारी अचानक फैलने के कारण स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। कोरोना महामारी ने स्वयं-सहायता समूहों की गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे इनके ऋण, बचत तथा आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिस कारण इन्हें कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। इस शोध-पत्र में कोरोना महामारी के दौरान स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया कि कोरोना महामारी के समय डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम के स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण निर्धन महिलाओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान दिया है। जरूरतमंदों के लिए मास्क बनाने से लेकर, सैनिटाइजर, हैंडवॉश, सुरक्षा कीट का निर्माण तथा सामुदायिक रसोई तथा सामुदायिक जागरूकता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. Salil Sagar, B. Dalela, V. S. Vats, P. A. Alvi, S. Dalela, Mitigation Template to contain COVID-19 in Indian Perspective: Post Lockdown, Bhumi Publication 2020, p.136
2. Deepak Kumar, Mitigating Socio-Economic impact of COVID-19: A collaborative approach of self-help groups (SHGs) and Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs), Bhumi Publication 2020, p.1746.
3. Mada Sarath Kumar, Mada Sai Gupta, Socio-Economic Impact of COVID-19 on India and World at Large, Bhumi Publication 2020, ISBN:978-93-88901-11-6
4. Gupta, Anchal,2020, India: Coronavirus (COVID-19) and Indian Economy, Retrieved May 20, 2020, from <https://www.mondaq.com/india/operational-impacts-and-strategy/936014/coronavirus-covid-19-and-indian-economy>
5. Mishra, Hari, Hara,2020, Self Help Group potential can boost rural production and consumption, retrieved, April08,2020, from <https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/fin>

वैश्विक कोरोना महामारी में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

ance/self-help-group--potential-can-boost-rural-production-and-consumption/articleshow/75004753.com?from=mdr

6. Government of India. (2020). COVID-19: NRLM Self Help Group women emerge as community warriors to contain the spread of COVID-19 in the country. Retrieved from <https://www.pallikkutam.com/edu-news/covid19-nrlm-self-help-group-women-emerge-as-community-warriors>
7. विमला देवी .(2020), 'ग्रामीण महिलाओं के सशक्त विकास में स्वयं सहायता समूह का योगदान व समूह का राजनितिक महत्व ,इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च , रिसर्च वोलुम -9 . पृष्ठ क्रमांक 2250-1991
8. कोविड-19 विशेषांक: ग्रामोदय संकल्प, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, अंक 1-संख्या 8, सितम्बर 2020
9. डॉ. नवीन कुमार . (2015), 'सामाजिक परिवर्तन में स्वयं सहायता समूह की भूमिका ,बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना
10. त्रिपाठी मधुसुदन (2011), ' भारत में महिला श्रमिक ' खुशी पब्लिकेशन, गाजियाबाद , पृष्ठ क्रमांक-24
11. सिंह निशांत (2011), 'स्त्री सशक्तिकरण एवं मूल्यांकन , खुशी पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्रमांक-17
12. कृष्णन , सि . (2011) " माइक्रोफाइनांस फॉर फाइनेंशियल ईन्क्लुजन एंड वुमेन एंपावरमेंट , इंटरनेशनल जनर्ल ऑफ विजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट , रिसर्च वोलुम-2 , (9) . पृष्ठ क्रामंक 135-150
13. कपूर , प्रमिला (2001) , " एम्पावरिंग द इण्डिया वुमेन" मिनिस्ट्री ऑफ इफोर्मेंशन एंड ब्रोडकास्टिंग , गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया
14. भारत में सूक्ष्म ऋण की स्थिति , नाबार्ड 2019-20
15. NRLM रिपोर्ट 2020
 - [HTTps://www.nabard.org/eng/ish/home.aspx](https://www.nabard.org/eng/ish/home.aspx)
 - www.rural.nic.in
 - <http://www.samacharnama.com>